भारत सरकार

योजना मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1789

दिनांक 29.07.2026 को उत्तर देने के लिए

गाजियाबाद में केंद्रीय कल्याण योजनाएं

1789. श्री अतुल गर्ग:

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गाजियाबाद निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय कल्याणकारी योजनाओं के पर्याप्तता स्तर का व्यवस्थित रूप से आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2025-26 के दौरान स्थानीय ग्रामीण ब्लॉकों में आवास, जल और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के वितरण के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) क्या इस मूल्यांकन में अल्पसेवित आवासीय क्षेत्रों में 100 प्रतिशत पर्याप्तता को रोकने के लिए विशिष्ट बाधाओं की पहचान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पंजीकरण प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए जिला प्रशासन को प्रदान की गई नीतिगत सिफ़ारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नागरिकों को स्थानीय योजना के कार्यान्वयन की प्रभावकारिता के बारे में रिपोर्ट देने की अनुमति देने के लिए समुदाय के नेतृत्व में लेखा परीक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए भविष्य में क्या कदम उठाए जाने की योजना है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं

राज्यमंत्री, संस्कृति मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) जी हां, सरकार देश में केन्द्रीय कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की नियमित रूप से निगरानी करती है।

(ख) गाजियाबाद के ग्रामीण ब्लॉकों में आवास, जल और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के संबंध में विवरण इस प्रकार है -

- प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (पीएमएवाई-जी): आवास प्लस 2024 सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) तैयार कर ली गई है।
- जल जीवन मिशन (जेजेएम) ग्रामीण: 87 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी गई है, 58 जलापूर्ति योजनाएं नियमित पाइप जलापूर्ति के साथ पूरी की गई हैं, जबकि 29 निर्माणाधीन हैं। 58,464 लक्षित घरों में से, 57,110 को पहले ही नल कनेक्शन प्राप्त हैं, जो लगभग परिपूर्णता को दर्शाता है। पेयजल गुणवत्ता निगरानी और निगरानी को एससीएडीए ऑटोमेशन सिस्टम के माध्यम से एकीकृत किया गया है।
- राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना: 2025-26 में, 5,050 नए पेंशनभोगियों की पहचान की गई और उन्हें मंजूरी दी गई। ग्रामीण क्षेत्रों में 2,032 नए आवेदनों की पहचान की गई और उन्हें मंजूरी दी गई।
- राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना: 2025-26 में जिले में 1389 आवेदन स्वीकृत किए गए, जिनमें से 416 आवेदन ग्रामीण क्षेत्रों से थे।
- दिव्यांग पेंशन योजना: 2025-26 में, 209 नए लाभार्थी जोड़े गए, जिससे कुल संख्या 1,501 हो गई।
- विशिष्ट दिव्यांगता आईडी कार्ड: 2025-26 में, 427 विकलांगता प्रमाणपत्र जारी किए गए, जिससे कुल संख्या बढ़कर 15,905 हो गई।
- स्थानीय स्तर की समिति योजना: 2025-26 में, 9 दिव्यांग व्यक्तियों को कानूनी संरक्षकता प्रमाण पत्र जारी किए गए, जिससे कुल पात्र व्यक्तियों की संख्या 61 हो गई।
- बेसहारा महिलाओं के लिए पेंशन योजना: 2025-26 में, 4,074 नए पेंशनभोगियों की पहचान की गई, जिसका कुल लाभ 43,332 महिलाओं को मिला।
- वन स्टॉप सेंटर योजना: 2025-26 में 1148 महिलाओं को सहायता प्राप्त हुई।

(ग) निगरानी के दौरान योजनाओं के कार्यान्वयन में किसी विशिष्ट बाधा की पहचान नहीं की गई है।

(घ) सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के तहत सभी प्रकार की पेंशन योजनाओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण या तो स्वतंत्र रूप से या जन सेवा लोकवाणी केंद्रों, साइबर कैफे और ग्राम सचिवालयों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (आवास प्लस सर्वेक्षण-2024) के तहत लाभार्थियों ने स्व-सर्वेक्षण किया है, जबकि ग्राम पंचायत सचिवों ने

'आवास प्लस 2024' मोबाइल ऐप का उपयोग करके ग्राम पंचायतों में सहायता प्राप्त सर्वेक्षण और पंजीकरण किया है।

(ङ) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत, एनआरएलएम के अंतर्गत संचालित एसएचजी नेटवर्क, गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) की सहायता से घर निर्माण की प्रगति और गुणवत्ता की निगरानी के लिए एक समुदाय-आधारित भागीदारी निगरानी प्रणाली शुरू करने का प्रावधान है।

****